भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौर

बेहतर भविष्य की सारी उम्मीदों का आधार यही है कि नवरात्रों से लेकर न्यू ईयर ईव तक आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार से इक०नमी की ठहरी हुई गाड़ी में ऐसा धक्का लगे कि वह स्टार्ट होकर फर्राटा भरने लगे। दिक्कत यह है कि अभी तक लोगों में त्योहारों को लेकर कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा है।

नवीन शाह।।

रिजर्व बैंक की नई मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की पहली बैठक के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने जो कुछ कहा उसका मूल स्वर यही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौर पीछे छूट चुका है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में 23. 9 फीसदी की ऐतिहासिक गिरावट के बाद अब चीजें धीरे–धीरे बेहतरी की ओर बढ़ रही हैं और आने वाले महीनों में यह प्रक्रिया ज्यादा तेज होगी। विभिन्न सेक्टरों में दिख रही रिकवरी को रेखांकित करते हुए रिजर्व बैंक ने उम्मीद जताई कि जनवरी–मार्च तिमाही में जीडीपी की वृद्धि सकारात्मक हो जाएगी, हालांकि पूरे वित्त वर्ष के लिए जीडीपी में 9.5 फीसदी की गिरावट का अनुमान है।

विश्व बैंक का आकलन इस आंकड़े के 9.6 फीसदी रहने का है। जितनी बुरी हालत इकॉनमी की हो गई थी, उसे देखते हुए यह तस्वीर अच्छी ही कही जाएगी। लेकिन इससे उत्साहित होते हुए भी इस बात पर जोर देना जरूरी है कि इन अनुमानों को सच बनाने की राह आसान नहीं है। इस राह पर पहला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव सामने खड़ा त्यौहारी सीजन है। बेहतर भविष्य की सारी उम्मीदों का आधार यही है कि नवरात्रों से लेकर न्यू ईयर ईव तक आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार से इकॉनमी की ठहरी हुई गाड़ी में ऐसा धक्का लगे कि वह स्टार्ट होकर फर्राटा भरने लगे। दिक्कत यह है कि अभी तक लोगों में त्योहारों को लेकर कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा है। मिडल क्लास के जिस हिस्से की नौकरी अभी बची हुई है, वह भी कम सेलरी पर काम करते हुए आने वाले महीनों में अपनी कंपनी के पे–रोल पर बने रहने की दुआ मांग रहा है।

आरबीआई सर्वे के मुताबिक करेंट सिचुएशन इंडेक्स (सीएसआई), जो जुलाई में 53.8 दर्ज किया गया था, सितंबर में और घटकर 49.9 हो गया। इस सर्वे में लोगों से उनका अभी का हाल–चाल पूछा जाता है। डेटा बता रहा है कि आधे से ज्यादा लोगों ने इसे खराब ही बताया है। जाहिर है, लॉकडाउन हटने के बाद भी खर्चे के मामले में आम उपभोक्ताओं के हाथ नहीं खुल रहे हैं। जरूरत लोगों को यह एहसास कराने की है कि इस डर के चलते बाजार सिकुड़ा रह जाएगा और नौकरियां जाने का खतरा और बढ़ जाएगा। इसके लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी तरफ से कोई नई पहलकदमी लेनी चाहिए। कुछ विशेषज्ञ एक खास समयसीमा में लैप्स हो जाने वाले ऐसे कूपन जारी करने का सुझाव दे रहे हैं, जिनसे त्यौहारी सीजन में खरीदारी करने से ग्राहकों को कुछ फायदा मिले। मिसाल के लिए, 10, 20 और 50 हजार के ऐसे डिजिटल कूपन जारी किए जाएं जिनसे 31 दिसंबर तक खरीदारी करने पर 12, 25 और 60 हजार के सामान खरीदे जा सकें। ऐसे दूसरे उपाय भी सोचे जा सकते हैं। अभी सबसे बड़ी जरूरत अर्थव्यवस्था में हलचल पैदा करने की है ताकि लोगों की नौकरियां सलामत रहें। यह सीजन अगर सूखा निकल गया और व्यापक छंटनी का चलन चल पड़ा तो आगे चलकर स्थितियों को संभालना और भी मुश्किल होता जाएगा।

सशक्त

अशोक वोहरा।

धर्म-दर्शन

जब आप अपनी जरुरत के अनुसार काम करते हो, तभी आप अपने आप को सशक्त बना सकते हो। कभी दूसरो से अपनेआप को भयभीत महसुस ना होने दे। कोई भी महान काम करने के लिये आपको किसी से भी इजाजत लेने की जरुरत नही है। सिर्फ इसलिए की वे बुद्धिमान है, उन्हें अपने सिर पर ना बिठाये। आप में भी बहुत अनुभव है और आप में उनसे भी महान सफलता हासिल कर सकते है। दूसरो को अपने से ज्यादा बुद्धिमानी मानना मतलब अपने विश्वास और हिम्मत को कम करना है। ऐसा करने से आपकी काबिलियत में भी कमी आएँगी क्योकि उस समय ऐसा सोचने लागोंगे की आप उनकी तरह अच्छे या महान नही है। हमेशा याद रखे, हर किसी को बदला जा सकता है और हर किसी को हराया जा सकता है। बल्कि आपको भी।

संपादकीय

113 दिन का राष्ट्रपति शासन

बनारसी दास की सरकार बर्खास्त होने के बाद यूपी में 113 दिन राष्ट्रपति शासन लगा रहा। इस वक्फे में कांग्रेस ने राज्य में वापसी की तैयारियां कीं तो इसी बीच नए चुनाव की घोषणा भी हुई। उस वक्त कांग्रेस के लिए सबसे सुकून की बात यह रही कि तब जनता पार्टी चार धड़ों में बंट चुकी थी। जनता पार्टी, जनता पार्टी जयप्रकाश, जनता पार्टी सेकुलर चरण सिंह और जनता पार्टी सेकुलर राजनारायण। मगर ये चारों पार्टियां कांग्रेस के बजाय आपस में ज्यादा लड़ रही थीं। इन चारों में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाली जनता पार्टी को ही उस चुनाव में सबसे ज्यादा 59 सीटें मिलीं थीं, लेकिन विशाल बहुमत तो कांग्रेस के ही हिस्से में गया। उस वक्त राज्य की विधानसभा में 425 सीटें हुआ करती थीं और कांग्रेस को 309 सीटों पर जीत मिली थी। केंद्र के बाद देश के सबसे बड़े राज्य में भी कांग्रेस की वापसी हो गई थी। कांग्रेसियों की मंशा थी कि संजय गांधी मुख्यमंत्री बनें। 1977 में कांग्रेस के पतन के लिए वही जिम्मेदार माने गए थे और 1980 में कांग्रेस की वापसी में उनके आक्रामक तेवरों को ही श्रेय दिया जा रहा था। खासतौर पर यूपी में उनके नेतृत्व में कांग्रेस सड़कों पर संघर्ष करती दिखी थी। यह वह दौर था, जब उनके नेतृत्व में युवा नेताओं की नई पौध तैयार हुई थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, और वीपी सिंह को मुख्यमंत्री चुना। उस वक्त वीपी सिंह की गिनती इंदिरा गांधी के विश्वसनीय लोगों में हुआ करती थी, संजय गांधी का भी उन्हें विश्वास हासिल था। वीपी सिंह का मुख्यमंत्री चुना जाना कांग्रेस की ओर से राज्य के जातीय समीकरणों में बदलाव की तरफ बढ़ाया जाने वाला कदम माना गया था। ज्यादातर मौकों पर ब्राह्मण मुख्यमंत्री देने वाली कांग्रेस ने ठाकुर चेहरे पर दांव लगाया था, जबकि एक समय कांग्रेस का जिताऊ समीकरण ब्राह्मण–मुस्लिम–दलित माना जाता था।

यह तय था कि जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी है और कांग्रेस ने वापसी कर ली है तो राज्यों में जनता पार्टी की सरकारों का ज्यादा चलना मुमकिन नहीं है।

मंत्री का शर्मसार होना

नदीम ।।

यह फरवरी 1980 का वाकया है। देश राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार के पतन के बाद एक बार फिर से इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की वापसी हो चुकी थी, लेकिन राज्यों में अभी इसकी शुरुआत होनी बाकी थी। यह तय था कि जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी है और कांग्रेस ने वापसी कर ली है तो राज्यों में जनता पार्टी की सरकारों का ज्यादा चलना मुमकिन नहीं है। यूपी में उस वक्त जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास थे। उन्हें मुख्यमंत्री बने एक साल हो रहा था। जून 1977 में जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री राम नरेश यादव हुए थे और फिर जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप ने उन्हें फरवरी 1979 में हटाकर बाबू बनारसी दास को मुख्यमंत्री बना दिया था। खैर, हम आते हैं उस कांड की तरफ, जो बाबू बनारसी दास की सरकार की बर्खास्तगी का कारण बना था। यूपी का एक जिला है देवरिया। उसका एक गांव हुआ करता था– नारायणपुर। अब यह गांव कुशीनगर जिले का हिस्सा हो चुका है। इस गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थीं, और उनके साथ दुर्भाग्य यह जुड़ा था कि उनके बेटे

की मौत हो चुकी थी और बहू ने घर छोड़ दिया था। ऐसे में दो छोटे पोते–पोतियों को पालने की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी, लेकिन एक रोज जब वे स्थानीय बाजार से गुजर रही थीं, तो एक बस से उनका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम करके पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद तो नारायणपुर में धीरे–धीरे हिंसा और आगजनी दौर शुरू हो गया। हालात इतने बिगड़े कि काबू पाने को पीएसी बुलानी पड़ी और गांव में बाकायदा उनका एक कैंप लगा दिया गया।

नारायणपुर गांव में जब पीएसी तैनात की गई तो सुबह गांव में यह कानाफूसी शुरू हो गई कि रात में पीएसी के जवानों ने गांव में औरतों के साथ दुराचार किया है। गांव से यह खबर निकल कर जिला मुख्यालय तक पहुंची, फिर राजधानी तक और उसके बाद 'नारायणपुर रेप कांड' राष्ट्रीय मुद्दे की शक्ल में बदल गया। यहीं से बाबू बनारसी दास सरकार की मुश्किलों का वह दौर शुरू हुआ, जिसकी कांग्रेस को बेसब्री से तलाश थी। बाबू बनारसी दास की मुश्किल तब और भी बढ़ गई, जब उन्हीं की सरकार में मंत्री मोहन सिंह नारायणपुर गांव पहुंचे और स्थानीय लोगों से मुलाकात के बाद उन्होंने बयान दिया, 'मुझे शर्म आ रही है कि मैं ऐसी सरकार में मंत्री हूं, जिसकी पुलिस ने नारायणपुर में दुष्कर्म जैसी घटना की।' इसके बाद तो उनकी सरकार की बर्खास्तगी की मांग शुरू हो गई। खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नारायणपुर पहुंचने का ऐलान कर दिया। एक प्रधानमंत्री का किसी बलात्कार की घटना में किसी गांव में पहुंचना एक बहुत बड़ी बात तो मानी ही जाती है। इंदिरा गांधी का नारायणपुर जाने का कार्यक्रम आने के बाद ही राजनीतिक गलियारों में यह माना जाने लगा था कि कुछ बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने वाला है। बाबू बनारसी दास ने स्थितियों को सामान्य बनाने की भरसक कोशिश की। सरकार के अंदर असंतुष्ट खेमे को सहेजा। स्थानीय लोगों से बयान भी दिलवाए कि राज्य सरकार ने अब तक जो कार्रवाई की है, उससे वे संतुष्ट हैं, लेकिन कोई भी कोशिश उनके लिए राहत का सबब नहीं बन पाई। इंदिरा गांधी ने कार्यक्रम के मुताबिक अपना दौरा किया और 17 फरवरी 1980 को बाबू बनारसी दास की सरकार बर्खास्त हो गई।

अष्टयोग-5203

	5	2	3	7		
1	33		40		34	6
7		4	6		2	3
	27	5	34	1	29	
2				4		5
	25	6	30		38	
	4		5	2		7

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है.खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं.गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी.सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5202 का हल

2	6	4	1	5	3	7
6	37	5	28	2	26	1
7	5	2	6	3	1	4
1	31	6	33	4	28	2
3	6	1	4	7	2	5
4	31	3	33	6	36	6
5	2	7	4	1	6	3

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

स्वीकार लेने के अलावा कोई चारा नहीं

मोहन। सात सितंबर, 1773 को वारेन हेस्टिंग्स लॉर्ड क्लाइव की जगह फिर गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने बनारस पहुंचकर शुजाउद्दौला को एक और संधि के लिए मजबूर कर दिया। इसके तहत शुजाउद्दौला से पचास लाख रुपये वसूलकर कड़ा व इलाहाबाद के इलाके उन्हें लौटा दिए गए। इस संधि की शर्तों में एक यह भी थी कि शुजाउददौला अपने सैनिकों की संख्या 35 हजार तक सीमित कर लेंगे और बाहरी हमलों से सुरक्षा के लिए कंपनी की सेना पर निर्भर करेंगे। यह सेना उनकी राजधानी में उनके ही खर्च पर रहेगी। इतना ही नहीं, उनके दरबार में कंपनी का एक रेजिडेंट भी रहेगा। यह अवध के राजकाज में कंपनी का सीधा दखल था, लेकिन शुजाउद्दौला के समक्ष चुपचाप इसे स्वीकार लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसलिए उन्हें अपनी राजधानी फैजाबाद में ब्रिटिश सेना के लिए छावनी व रेजिडेंट के लिए आवास तामीर कराने ही पड़े।